

**INDEX**  
**STARRED ASSEMBLY QUESTION No.\* 22**  
**Listed on 09.08.2022**

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Reply of Assembly Question No. *22 (in English)	1
2.	Reply of Assembly Question No. *22 (in Hindi)	2

## **Compensation of Land Acquired**

\*22

**Sh. SATYA PRAKASH (Pataudi):**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) whether there is any proposal under consideration of the Government to release the 1810 Acre land of Kasan and other villages in District Gurugram or to give best compensation to the farmers for their acquired land; and
- b) the policy of the government for the rehabilitation of farmers whose land has been acquired?

**Reply:-**

**Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.**

- a) Sir, there is no such proposal of the Government to release the land measuring 1810 acres of villages Kasan, Kukrola and Sehrawan, tehsil Manesar, district Gurugram and the compensation will be given to the landowners as per the law.
- b) The State Government in the Revenue and Disaster Management Department issued the Rehabilitation and Resettlement Policy, 2010, vide notification dated 09.11.2010. As per this policy, residential plots are allotted to the eligible landowners in lieu of their acquired land.

\*\*\*\*

## भूमि अधिग्रहण का मुआवजा

\*22 श्री सत्य प्रकाश (पटौदी) :

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या जिला गुरुग्राम में कासन तथा अन्य गांवों की 1810 एकड़ भूमि को विमुक्त करने या किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए अच्छा मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) किसानों, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, के पुनर्वास के लिए सरकार की नीति क्या है?

उत्तर:-

दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा।

(क) श्रीमान् जी, गांव कासन, कुकरोला तथा सहरावन, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम की 1810 एकड़ भूमि को छोड़ने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है तथा भू-मालिकों को कानून के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना दिनांक 09.11.2010 के तहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2010 जारी की थी। इस नीति के तहत, पात्र भू-मालिकों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले, आवासीय प्लॉट आवंटित किये जाते हैं।

\*\*\*\*\*